भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1278
सोमवार,11फरवरी,2019/22माघ,1940 (शक)

रोजगार में कमी

1278. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजराः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे किः

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान देश मेंसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में 3.5 मिलियनरोजगार के अवसर कम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त अवधिके दौरान जिन औद्योगिकऔर विनिर्माण क्षेत्रों, जहां रोजगार के अवसर कमहुए हैं, के नाम और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में ऐसे क्षेत्रों कीपहचान की है जहां भविष्य में रोजगार के अवसरसृजित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौराक्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ):सरकार एमएसएमई क्षेत्रों के संबंध इस तरह के किसी भी आंकड़े से अवगत नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालयने अपने 73 वें चरण (जुलाई, 2015 - जून, 2016) के दौरान अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) का एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमईक्षेत्र में कुल 1109.89 लाख रोजगार हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में उत्पादकता को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा एवं रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाया है।

इसके अलावा, मंत्रालय एमएसएमई को मजबूत करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मिशन सोलर चरखा, पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई), नवपरिवर्तन ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, (एएसपीआईआरई), क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी), मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम और एमएसई-क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि शामिल हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण को 2016 के दौरान 10 या अधिक श्रमिक वाले संगठित उद्योगों / क्षेत्रों में उद्यमों के विस्तारित कवरेज के साथ सुधारा गया। आठ व्यापक संगठित क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, आवास और रेस्तरां, आईटी/बीपीओ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हैं। जुलाई, 2016 से अक्टूबर, 2017 तक इन आठ क्षेत्रों में रोजगार में हुए परिवर्तन अनुबंध में दिए गए हैं।

मेक इन इंडिया एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे निवेश को सुकर बनाने, नई खोज को बढ़ावा देने, कौशल का विकास करने और बौद्धिक सम्पदा और निर्माण संबंधी ढांचागत सुविधाओं का सर्वोत्तम निर्माण करने के लिए तैयार किया गया है। मेक इन इंडिया परियोजना में 25 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें रोजगार अवसरों के सृजन हेतु विमानन, निर्माण, चमड़ा, वस्त्र और पोशाक, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोबाइल, ऑटो के कलपुर्जे, खाद्य प्रसंस्करण, सड़कें और राजमार्ग, खनन, आईटी और बीपीएम आदि शामिल हैं।

अनुबंध

रोजगार में कमीके संबंध में लोक सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित त्वरित तिमाही रोजगार सर्वेक्षणों के अनुसार आठ क्षेत्रों में रोजगार में क्षेत्र-वार परिवर्तन

(लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1 अप्रैल, 2016 को स्तर अनुमान	1अप्रै. 16की तुलना में 1जुला., 16	1जुला. 16की तुलना में 1अक्तू., 16	1अक्तू. 16की तुलना में 1जन. 17	1जन., 17की तुलना में 1अप्रै., 17	1अप्रै., 17की तुलना में 1जुला., 17	1 जुलाई, 17 की तुलना में 1अक्तूबर, 17
1	विनिर्माण	101.17	-0.12	0.24	0.83	1.02	-0.87	0.89
2	निर्माण	3.67	-0.23	-0.01	-0.01	0.02	0.10	-0.22
3	व्यापार	14.45	0.26	-0.07	0.07	0.29	0.07	0.14
4	परिवहन	5.8	0.17	0.00	0.01	0.03	-0.03	0.20
5	आवास और रेस्तरां	7.74	0.01	-0.08	0.00	0.03	0.05	0.02
6	आईटी/बीपीओ	10.36	-0.16	0.26	0.12	0.13	0.02	0.01
7	शिक्षा	49.98	0.51	-0.02	0.18	0.02	0.99	0.21
8	स्वास्थ्य	12.05	0.33	0.00	0.02	0.31	0.31	0.11
	कुल	205.22	0.77	0.32	1.22	1.85	0.64	1.36

*स्रोतः श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय